around Rs. 150/- in contrast to lower rates at which private operators claim to supply?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir. Parallel marketers have not been able to supply LPG to domestic consumers in any significant way so far.

(b) Lack of LPG import facilities is the main constraint in the progress of LPG marketing under Parallel Marketing System. To the extent possible, facilities of Pubic Sector Oil Companies have been made available to the Parallel Marketters on commercial terms. However some private parties have initiated action to develop their own import facilities.

(c) The subsidy on a LPG cylinder of 14.2 Kgs. for a domestic use being marketed by Government oil companies is around Rs. 56/- per cylinder. Parallel marketeers can sell their product at their own prices.

**तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के काम को मद्रास की एक फर्म को देना**

184. **श्री ईशदत्त यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का काम इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित किए बगैर मद्रास की अज्ञात लायड फर्म को सौंप दिया है जबकि उक्त फर्म तकनीकी रूप से इस काम को करने में अक्षम है ;

(ख) निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर और इस संबंध में फर्म की तकनीकी सक्षमता की जांच किए बगैर उक्त फर्म को काम सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सबंध में खर्च की गई राशि के साथ उक्त फर्म द्वारा अब तक संपन्न किए गए काम का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने इसके अपने वेधन/कार्यनिष्पादन प्रचालनों के लिए 3 रिगों यथा जी.ए.–ii, जी.ए.–iii इले डी. एण्डडरम, भाड़े पर लेने हेतु मैसर्स अज्ञान लाइड चाइल्ज आफ शोर लि० को संविदा दी। इनमें से जी.ए.–ii ने वेधन कार्य पूरा कर लिया है तथा इस रिग के प्रति फर्म को लगभग 68.50 करोड रुपए का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। अन्य दो रिगों द्वारा वेधन/कार्य निष्पादन संबंधी प्रचालन अभी भी जारी है तथा इन दो रिगों के प्रति फर्म को लगभग 97.53 करोड़ रुपए तथा 6.87 मि. अमरीकी डालर का कुल भुगतान किया गया है ।

**डीजल शेड के संबंध में अनुमोदन**

185. **श्री आस मोहम्मद :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1991–92 के दौरान डीजल शेड के संबंध में अनुमोदन को समाप्त कर दिया गया ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जहां पर डीजल शेड इस समय स्थित हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं और उनकी पृथक पृथक क्षमता कितनी है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :** (क) से (ग) तेल उद्योग के अन्तर्गत

"पंजल शेड" जैसी कोई शब्दावली अथवा परियोजना नहीं है। तथापि, वर्तमान में एच.एस.डी. के संबंध में देश में 3.42 मि. मी. टन भंडार क्षमता के 83 तेल डिपो टर्मिनल है।

**संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र**

186. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
**श्री आस मोहम्मद :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 4 मई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5742 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 के दौरान संसद् सदस्यों से प्राप्त 1406 पत्रों के उत्तर नहीं दिए गए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने संबंधित मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर दिए जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई ,

(ग) क्या सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करके उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जो सरकारी पत्रों के उत्तर न देने के दोषी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :** (क) और (ख) सांसदों के 31-3-94 तक प्राप्त पत्रों में से जो पत्र उस तारीख तक अनुत्तरित रह गए थे अब केवल 216 पत्र लंबित हैं। यह इसलिए लंबित हैं कि अधिकांश मामलों में पत्रों में उठाए गए मामले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से नहीं निपटाए जा सकते। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र संगठनों से आंकड़े अथवा अद्यतन जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है इसमें काफी समय लगता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनजर इन अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Agreement of IOC with Raaj Unocal Ltd.**

187. SHRI NILOTPAL BASU :
SHRIMATI SARLA MAHESHWARI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether IOC has signed an agreement with Raaj Unocal Ltd. Delhi, for blending and packaging of lubes, if so, what is the blending fee offered by IOC to the party;

(b) what is the blending fee paid by IOC to Indian Oil Blending Ltd. (IOBL) a subsidiary of IOC;

(c) what had been the stock lubricants maintained at Delhi and other northern region terminal depots for the year ending 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(d) on how many occasions did IOC ail to meet the customer, requirement of automotive engine oil in northern sector before the agreement with the private party; and

(e) in what manner IOC/IOBL are protecting the formulation developed for blending base oil with additives after allowing the private party to blend the product?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir. The IOC will pay a blending fee of Rs. 1120 per KL to the Party.

(b) The Blending fee payable to the IOBL is Rs. 440 per KL, which is being